

संख्या:-/XXVII(1)/06-07

प्रषक,

एलएएम पन्त,
अपर सचिव, (वित्त),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

विषय:- 12वाँ वित्त आयोग की संसृति पर वर्ष*2006-07 के लिए समस्त क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित
देहरादून: दिनांक: 20 : मार्च, 2007

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-1659 सी/XXVII(1)/2006 दिनांक 09 नवम्बर, 2006

का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा ₹0 486000000.00 (₹0 चार करोड़ छियासी लाख मात्र) की धनराशि

समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 2-

(4) "क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु खण्ड विकास

अधिकारी द्वारा तैयार किए जायें तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा" के स्थान

पर "संक्रमित की जा रही धनराशि का बिल जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किया

जायेगा और जिलाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करार कोषागार से धनराशि आहरित कर सम्बन्धित विकास

खण्ड को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।" पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(एलएएम पन्त)

अपर सचिव, वित्त।

संख्या:-233 (1)/XXVII(1)/06-07, तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कांदावाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।

2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँक मण्डल, उत्तराखण्ड।

3- निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4- समस्त जिला पंचायत राज, अधिकारी, उत्तराखण्ड।

5- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

6- निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय अथ विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, प्रथम तल

सी०जी०आ० कामपलेक्स, नई दिल्ली।

7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8- निजी सचिव, मा० मुख्यामंत्री जी, उत्तराखण्ड।

9- एन०आइ०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

25/3/2007
(एलएएम पन्त)
अपर सचिव, वित्त